



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 73]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 11, 2014/फाल्गुन 20, 1935

No. 73]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 11, 2014/PHALGUNA 20, 1935

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मार्च, 2014

**विषय :** चीन जन.गण, कोरिया गण और मलेशिया के मूल के या वहां से निर्यातित स्टेनलैस स्टील 304 श्रृंखला के कुछेक हॉट रोल्ड फ्लैट उत्पादों के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के लिए जांच की शुरुआत ।

**सं. 14/30/2013-डीजीएडी.**—मै0 जिंदल स्टेनलैस लिमिटेड, नई दिल्ली ने चीन जन.गण., कोरिया गण. और मलेशिया (जिन्हें आगे संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के या वहां से निर्यातित ए एस टी एम ग्रेड 304 के स्टेनलैस स्टील के हॉट रोल्ड फ्लैट उत्पादों और उनके सभी परिवर्तों (जिसे आगे संबद्ध वस्तु कहा गया है) के आरोपित पाटन के बारे में पाटनरोधी जांच शुरु करने के लिए समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं का अभिज्ञान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली कहा गया है), के अनुसार, निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे प्राधिकारी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है ।

2. और यतः प्राधिकारी ने यह पाया है कि संबद्ध देशों द्वारा संबद्ध वस्तु के पाटन, घरेलू उद्योग को हुई क्षति और पाटन एवं क्षति के बीच कारणात्मक संबंध का पर्याप्त साक्ष्य मौजूद है; अतः प्राधिकारी आरोपित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने और पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश करने जिसे यदि लागू किया जाएगा तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, के लिए उक्त नियमावली के नियम 5 के अनुसार, आरोपित पाटन और घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति के बारे में एतद्वारा जांच शुरु करते हैं ।

## विचाराधीन उत्पाद

3. वर्तमान याचिका में विचाराधीन उत्पाद "हॉट रोल्ड आस्टेनिटिक स्टेनलैस स्टील के फ्लैट उत्पाद; चाहे वे यूएनएस, डीआईएन, जेआईएस, बीआईएस, ईएन आदि जैसे किसी अन्य मानकों में 304 अथवा 304 एच अथवा 304 एल अथवा 304 एन अथवा 304 एलएन अथवा ईएन 1.4311, ईएन 1.4301, ईएन 1.4307 अथवा एक्स 5 सीआरएनआई 1810 अथवा एक्स 04 सीआर 19 एनआई 9 अथवा उनके समतुल्यों के ग्रेड के रेक्टेंगुलर आकार की प्लेटें, शीट अथवा क्वायल (हॉट रोल्ड एनीलैड और पिकलड अथवा ब्लैक) हों अथवा नहीं ; चाहे एक संख्या के हों अथवा ब्लैक फिनिश हों; चाहे गुणवत्ता की दृष्टि से प्रमुख हों अथवा नहीं; चाहे मिल एज या ट्रिम एज के साथ एज कंडीशन के हों अथवा नहीं; जिनकी मोटाई क्वायलों में 1.2 मिमी0 से 10.5 मिमी0 के बीच हो और प्लेटों और शीटों में 3 मिमी. से 105 मिमी. की हो; जिनकी चौड़ाई 1650 मिमी0 तक हो; जिनकी क्वायलों में सभी लंबाई 10,000 मीटर तक की हो और प्लेटों में 10 मीटर तक की हो ।"

4. संबद्ध वस्तु का उपयोग प्रोसेस उपकरणों के विनिर्माण, रिरोलिंग, रिएक्टर वैसलों, सामग्री हैंडलिंग उपकरणों, रेलवे, पाइप एवं ट्यूबों, ऑटोमोटिव संघटकों, रोल्ड फॉर्मड सेक्सनों, वास्तुकला, भवन एवं निर्माण, औद्योगिक फैब्रिकेशन, विद्युत क्षेत्र आदि में किया जाता है । घरेलू उत्पाद के अनिवार्य उत्पाद संबंधी गुणधर्मों, उत्पाद के अनिवार्य गुणधर्मों के रूप में आयातित वस्तु के समनुरूप हैं ।

5. संबद्ध वस्तु सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 72 के सीमाशुल्क उपशीर्ष 7219 तथा 7220 के अंतर्गत वर्गीकृत है। तथापि, यह वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर किसी भी रूप में बाध्यकारी नहीं है।

### **समान वस्तु**

6. आवेदक ने दावा किया है कि उनके द्वारा उत्पादित वस्तु संबद्ध देशों के मूल की या वहां से निर्यातित वस्तु के "समान वस्तु" है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तु में भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं, कार्य एवं उपयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण एवं विपणन और टैरिफ वर्गीकरण आदि जैसे मापदंडों के रूप में तुलनीय विशेषताएं हैं। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु उत्पाद के अनिवार्य गुणधर्मों के रूप में आयातित वस्तु के समानरूप है। अतः जांच के प्रयोजनार्थ आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को पाटनरोधी नियमों के अर्थ के भीतर संबद्ध देशों से आयातित वस्तु के समान वस्तु माना जा रहा है।

### **घरेलू उद्योग**

7. यह आवेदन मै0 जिंदल स्टेनलैस लि0, नई दिल्ली द्वारा दायर किया गया है। आवेदक ने वर्तमान जांच से संगत सूचना प्रदान की है। आवेदक कंपनी का उत्पादन भारत में उत्पादित समान उत्पाद के कुल उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है। यह भी नोट किया जाता है कि आवेदक ने विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है और न ही वह विचाराधीन उत्पाद के किसी आयातक या निर्यातक से संबंधित है। अतः यह निर्धारित किया जाता है कि यह आवेदन घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उसकी ओर से किया गया है और आवेदन पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के अंतर्गत "आधार" संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करता है। इसके अलावा, आवेदक पाटनरोधी नियमावली के नियम 2 (ख) के अनुसार "घरेलू उद्योग" है।

### **शामिल देश**

8. वर्तमान जांच में शामिल देश चीन जन.गण., कोरिया गण और मलेशिया हैं।

### **सामान्य मूल्य**

9. आवेदक ने दावा किया है कि चीन जन.गण. को गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना जाना चाहिए और इसलिए सामान्य मूल्य का निर्धारण नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 और 8 के अनुसार किया जाना चाहिए। आवेदक ने अनुरोध किया है कि वह बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में किसी उत्पादक से ऐसी सूचना प्राप्त करने में समर्थ नहीं रहा है और इसलिए उसने विधिवत समायोजित भारत में उत्पादन लागत के आधार पर चीन जन.गण. में सामान्य मूल्य निर्धारित किया है।

10. जहां तक कोरिया गणराज्य और मलेशिया के लिए सामान्य मूल्य का संबंध है, आवेदक ने अनुरोध किया है कि संबद्ध देशों के घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तु की कीमत के बारे में सूचना/साक्ष्य प्राप्त करने के प्रयास किए गए थे। तथापि, आवेदक ऐसी सूचना प्राप्त करने में समर्थ नहीं रहा था। अतः आवेदक ने विधिवत समायोजित भारत में उत्पादन लागत के आधार पर समस्त संबद्ध देशों के लिए सामान्य मूल्य परिकलित किया है।

11. प्राधिकारी ने आवेदक के दावे की जांच की है और यह नोट करते हैं कि संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु का पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य है।

### **निर्यात कीमत**

12. भारत में आयातों की मात्रा और मूल्य का निर्धारण करने के लिए आवेदकों ने गौण स्रोत, आईबीआईएस, मुंबई से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर विचाराधीन उत्पाद के लिए निर्यात कीमत का दावा किया है। समुद्री भाड़े, समुद्री बीमा, कमीशन, पत्तन व्यय, अंतरदेशीय भाड़ा व्यय, बैंक प्रभार, वैट अंतर (केवल चीन के लिए) के कारण कीमत समायोजन किए गए हैं। संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु की निवल निर्यात कीमत का पर्याप्त प्रथमदृष्टया साक्ष्य है।

### **पाटन मार्जिन**

13. आवेदक ने इस आशय का पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध कराया है कि संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य निवल निर्यात कीमत से काफी अधिक है जिससे प्रथम दृष्टया यह संकेत मिलता है कि पाटनरोधी जांच को न्यायोचित ठहराने के लिए संबद्ध देशों के मूल की या वहां से निर्यातित और पाटित की जा रही संबद्ध वस्तु का भारत में पाटन किया जा रहा है।

### **क्षति एवं कारणात्मक संबंध**

14. आवेदक ने दावा किया है कि उसे वास्तविक क्षति हुई है और उसने आयातों में समग्र रूप में हुई वृद्धि, बिक्री, बाजार हिस्से में सुधार की कमी, क्षमता संवर्धन के बावजूद उत्पादन एवं क्षमता उपयोग अपेक्षित स्तर तक न होने तथा अन्य स्रोतों पर पाटनरोधी शुल्क लागू होने एवं लाभ, लगाई गई पूंजी पर आय और नकद लाभ आदि में गिरावट आने के रूप में संबद्ध देशों से हुए आरोपित पाटन के परिणामस्वरूप हुई क्षति के बारे में साक्ष्य प्रस्तुत किया है।

15. आवेदक ने कीमत न्यूनीकरण और कीमत कटौती से स्पष्ट हुए प्रतिकूल कीमत प्रभावों का भी दावा किया है। प्राधिकारी यह मानते हैं कि पाटनरोधी जांच की शुरुआत को न्यायोचित ठहराने के लिए संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के कारण आवेदक को हो रही "क्षति" का पर्याप्त साक्ष्य है।

### **जांच की शुरुआत**

16. प्राधिकारी ने यह पाया है कि पाटनरोधी जांच की शुरुआत को न्यायोचित ठहराने के लिए संबद्ध देशों के मूल की या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन, घरेलू उद्योग को हुई "क्षति" और "पाटन एवं क्षति" के बीच कारणात्मक संबंध का पर्याप्त साक्ष्य मौजूद है। प्राधिकारी आरोपित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने और पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश करने जिसे यदि लागू किया जाएगा तो वह घरेलू उद्योग को हुई "क्षति" को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, के लिए पाटनरोधी नियमावली के नियमों के अनुसार, आरोपित पाटन और घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति के बारे में एतद्वारा जांच शुरू करते हैं।

**जांच अवधि**

17. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच अवधि अप्रैल, 2012 – जून, 2013 (15 माह) तक की है। तथापि, क्षति जांच अवधि में अप्रैल 2009 – मार्च 2010, अप्रैल, 2010 – मार्च, 2011, अप्रैल, 2011 – मार्च, 2012 की अवधि और जांच अवधि शामिल होगी।

**सूचना प्रस्तुत करना**

18. संबद्ध देशों में ज्ञात निर्यातकों, भारत में उसके दूतावास के जरिए उसकी सरकार, विचाराधीन उत्पाद से संबंधित समझे जाने वाले भारत में आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को निर्धारित प्रपत्र में एवं ढंग से संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से लिखा जा रहा है। कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे निर्धारित समय सीमा के भीतर इस जांच से संगत अपने अनुरोध कर सकता है और निम्नलिखित पते पर लिख सकता है:

**निर्दिष्ट प्राधिकारी**

**पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय**

**भारत सरकार**

**वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,**

**वाणिज्य विभाग,**

**उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011**

**समय-सीमा**

19. इस जांच से संबंधित कोई सूचना लिखित में भेजी जानी चाहिए जो इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 40 दिनों से पूर्व उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास पहुंच जानी चाहिए। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी है तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमों के अनुसार, “उपलब्ध तथ्यों” के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

**गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना**

20. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 (7) के अनुसार हितबद्ध पक्षकारों के लिए प्राधिकारी को प्रदत्त किसी गोपनीय सूचना का अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करना अपेक्षित है और ऐसी सूचना प्रदाता पक्षकार की राय यह है कि ऐसी सूचना का सारांश प्रस्तुत करना संभव नहीं है तो उसके कारण का एक विवरण उपलब्ध कराना अपेक्षित है।

21. यदि प्रश्नावली के उत्तर/अनुरोधों के किसी भाग के बारे में गोपनीयता का दावा किया जाता है तो उसे दो अलग-अलग सैटों (क) गोपनीय रूप में अंकित (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि) और (ख) अगोपनीय रूप में अंकित दूसरा सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि) में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। प्रस्तुत की गई समस्त सूचना पर प्रत्येक पृष्ठ के सबसे ऊपर स्पष्ट रूप से “गोपनीय” या “अगोपनीय” अंकित होना चाहिए।

22. किसी गोपनीय अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। गोपनीय रूपांतरण और अगोपनीय रूपांतरण प्रत्येक की दो (2) प्रतियां प्रस्तुत की जानी चाहिए।

23. गोपनीय रूप में दावा की गई सूचना हेतु: सूचना प्रदाता के लिए यह अपेक्षित है कि वह प्रदान की गई सूचना के साथ इस आशय के यथोचित कारण का एक विवरण उपलब्ध कराए कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता और/अथवा ऐसी सूचना का सारांश क्यों संभव नहीं है।

24. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई/सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को समुचित ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है; तो प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांश क्यों संभव नहीं है।

25. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

26. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी रिकॉर्ड में नहीं ले सकते हैं। संतुष्ट होने और प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत को स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

27. उपर्युक्त पैरा में किसी बात के होते हुए भी यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

**सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण**

28. नियम 6(7) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी सार्वजनिक फाइल रखते हैं। कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

**असहयोग**

29. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं ।

जे. एस. दीपक, निर्दिष्ट प्राधिकारी

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY****(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)****INITIATION NOTIFICATION**

New Delhi, the 11th March, 2014

**Sub:- Initiation of investigation for imposition of anti-dumping duty on imports of certain Hot-Rolled Flat Products of Stainless Steel 304 series originating or exported from China PR, Republic of Korea and Malaysia.**

**No. 14/30/2013-DGAD.**—M/s Jindal Stainless Limited, New Delhi have filed an application before the Designated Authority (herein after referred to as the Authority) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on dumped articles and for determination of injury) Rules, 1995 (herein after referred to as Rules) for initiation of anti dumping investigation concerning alleged dumping of certain Hot Rolled Flat Products of Stainless Steel of ASTM Grade 304 with all its variants (hereinafter referred to as subject goods) originating in or exported from China PR, Republic of Korea and Malaysia (hereinafter referred to as subject countries) .

2. AND WHEREAS, the Authority finds that sufficient prima facie evidence of dumping of subject goods by the subject countries, injury to the domestic industry and causal link between the dumping and injury exist, the Authority hereby initiates an investigation into the alleged dumping, and consequential injury to the domestic industry in terms of the Rules 5 of the said Rules, to determine the existence, degree and effect of alleged dumping and to recommend the amount of antidumping duty, which if levied would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

**Product under consideration**

3. The product under consideration in the present petition is “Hot Rolled austenitic stainless steel flat products; whether or not plates, sheet or coils (hot-rolled Annealed and Pickled or Black) of rectangular shape; of grade either 304 or 304H or 304L or 304N or 304LN or EN 1.4311, EN 1.4301, EN 1.4307 or X5CRNI1810 or X04Cr19Ni9, or equivalents thereof in any other standards such as UNS, DIN, JIS, BIS, EN, etc.; whether or not with number one or Black finish; whether or not of quality prime or non prime; whether or not of edge condition with mill edge or trim edge; of thickness in the range of 1.2mm to 10.5mm in Coils and 3mm to 105mm in Plates & Sheets; of all widths up to 1650 mm; of all lengths up to 10,000 meters in Coils and 10 Meters in Plates.”

4. The subject goods are used for manufacture of process equipments, re-rolling, reactor vessels, material handling equipments, railways, pipes & tubes, automotive components, rolled formed sections, architecture, building & construction, industrial fabrication, power sector, etc. Essential product properties of domestic product are identical to the imported goods in terms of essential product properties.

5. The subject goods is classified Chapter 72 of the Customs Tariff Act, 1975, under customs sub-heading 7219 and 7220. The classification is however only indicative and in no way binding on the scope of the present investigation.

**Like Articles**

6. The applicant has claimed that the goods produced by them are “like articles” to the goods originating in or exported from the subject countries. The subject goods produced by the domestic industry and imports from subject countries have comparable characteristics in terms of parameters such as physical & chemical characteristics, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification, etc. Subject goods produced by the domestic industry are identical to the imported goods in

terms of essential product properties. Therefore, for the purpose of investigation, the subject goods produced by the applicant are being treated as like articles to the goods imported from subject countries within the meaning of the Anti Dumping Rules.

### **Domestic Industry**

7. The application has been filed by M/s Jindal Stainless Limited, New Delhi. The applicant has provided information relevant to the present investigation. The production of the applicant company constitutes a major proportion in total production of the like product produced in India. It is also noted that applicant has not imported the product under consideration, nor are they related to an importer or exporter of the product under consideration. It is thus determined that the application has been made by or on behalf of the domestic industry and the application satisfies the requirements of 'standing' under Rule 5 of the AD Rules. Further, the Applicant constitutes 'Domestic Industry' in terms of Rule 2(b) of the AD Rules.

### **Countries involved**

8. The countries involved in the present investigation are China PR, Republic of Korea and Malaysia.

### **Normal Value**

9. The Applicant has claimed that China PR should be treated as Non-Market Economy and therefore the normal value should be determined in accordance with Para 7 and 8 of Annex-I of the Rules. Applicant has submitted that it not been able to procure such information from a producer in market economy third country and has therefore determined Normal Value in China PR on the basis of cost of production in India duly adjusted.

10. As regards normal value for Republic of Korea and Malaysia, the Applicant has submitted that efforts were made to get information/evidence of price of subject goods in the domestic market of subject countries. However, Applicant was not able to get such information. The Applicant has therefore constructed normal value for all subject countries on the basis of cost of production in India duly adjusted.

11. The Authority examined the claim of the Applicant and notes that there is sufficient prima facie evidence of normal value of the subject goods in the subject countries.

### **Export Price**

12. The applicants have claimed export price for product under consideration based on the data procured from secondary source, IBIS, Mumbai to assess the volume and value of imports in India. Price adjustments have been made on account of ocean freight, marine insurance, commission, port expenses, inland freight expenses, bank charges, VAT difference (only for China). There is sufficient prima facie evidence of net export price of the subject goods in the subject countries

### **Dumping Margin**

13. The applicant has provided sufficient evidence that the normal values of the subject goods in the subject countries are significantly higher than the net export prices, prima-facie indicating that the subject goods originating in or exported from the subject countries are being dumped, to justify initiation of an antidumping investigation.

### **Injury and Causal Link**

14. The applicant has claimed that they have suffered material injury and have furnished evidence regarding injury having taken place as a result of the alleged dumping from subject countries in terms of increase in imports in absolute terms, lack in improvement of sales, market share, production and capacity utilization to the expected levels despite addition of capacities and imposition of anti dumping duties on other sources and significant deterioration in profits, return on capital employed and cash profit etc.

15. The applicant has also claimed adverse price effects as evidenced by price depression and price undercutting. The Authority considers that there is sufficient evidence of 'injury' being suffered by the applicant caused by dumped imports of subject goods from subject countries to justify initiation of an antidumping investigation.

**Initiation of Investigations**

16. The Authority finds that sufficient prima facie evidence of dumping of the subject goods originating in or exported from the subject countries, 'injury' to the domestic industry and causal link between the dumping and 'injury' exist to justify initiation of an anti-dumping investigation. The Authority hereby initiates an investigation into the alleged dumping, and consequent injury to the domestic industry in terms of the Rules of the AD Rules, to determine the existence, degree and effect of alleged dumping and to recommend the amount of antidumping duty, which if levied would be adequate to remove the 'injury' to the domestic industry.

**Period of Investigation**

17. The period of investigation (POI) is April, 2012 – June, 2013 (15 months) for the purpose of present investigation. The injury investigation period will however cover the periods April 2009-March 2010, April 2010-March 2011, April 2011 to March 2012 and the POI.

**Submission of information**

18. The known exporters in the subject countries and their Governments through their Embassies in India, importers and users in India known to be concerned and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all information relevant in the form and manner prescribed. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation within the time-limit set out below and write to:

**The Designated Authority**  
**(Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties)**  
**Government of India**  
**Ministry of Commerce & Industry**  
**Department of Commerce**  
**Udyog Bhavan, New Delhi-110011.**

**Time limit**

19. Any information relating to this investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the above address not later than 40 days from the date of publication of this notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record their findings on the basis of the 'facts available' on record in accordance with the AD Rules.

**Submission of Information on Non-Confidential basis**

20. In terms of Rule 6(7) of the Anti-dumping Rules, the interested parties are required to submit non-confidential summary of any confidential information provided to the Authority and if in the opinion of the party providing such information, such information is not susceptible to summarization, a statement of reason thereof, is required to be provided.

21. In case confidentiality is claimed on any part of the questionnaire's response/submissions, the same must be submitted in two separate sets (a) marked as Confidential (with title, index, number of pages, etc.) and (b) other set marked as Non-Confidential (with title, index, number of pages, etc.). All the information supplied must be clearly marked as either "confidential" or "non-confidential" at the top of each page.

22. Information supplied without any mark shall be treated as non-confidential and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect any such non confidential information. Two (2) copies each of the confidential version and the non confidential version must be submitted.

23. For information claimed as confidential, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed and/or why summarization of such information is not possible.

24. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out / summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional

circumstances, party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible of summary; a statement of reasons why summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.

25. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

26. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim may not be taken on record by the Authority. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such confidential information.

27. Notwithstanding anything contained in para above, if the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in a generalised or summary form, it may disregard such information.

### **Inspection of Public File**

28. In terms of rule 6(7) any interested party may inspect the public file containing non-confidential versions of the evidence submitted by other interested parties.

### **Non-cooperation**

29. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Governments as deemed fit.

J. S. DEEPAK, Designated Authority